(b) Indigenous coal production is by and large adequate to meet the overall demand of various consumers except the steel plants. It cannot be said with certainty at this stage as to how much coking coal will be imported in the current year, since it is contingent on factors like availability of foreign exchange, etc.

(c) The Ministry of Coal is taking following steps to improve supply of coal to thermal power stations:—

(i) Production of coal by coal companies is being monitored on daily basis, and efforts are being made to meet the production targets.

(ii) Efforts are being made to step up despatch of coal to the thermal power stations by increasing rail loading and ensuring maximum supply through other means like road, conveyor belt etc.

(iii) Coal supply to power houses is being monitored regularly and appropriate action is being taken immediately to meet any deficit.

Demand for a balanced policy on Textiles

349. SHRI A. G. KULKARNI:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the reasons for which export of cotton yarn has been banned w.e.f. 20th September, 1991, when there is no scarcity;

(b) whether the Ministry will follow a balanced policy on "Textile" Industry as regards cotton exports, availability of yarn to decentralised sector and exports of cotton cloth, yarn, apparels; what are the proposals in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) In order to ameliorate the difficulties of decentralised handloom and powerloom weavers arising out of high prices declining availability of cotton yarn, Government have suspended cotton yarn exports with effect from 21st September 1991. However, the following categories of exports were later exempted from the suspension order:—

(i) Exports under Advance Licensing 100% per cent EOU Scheme.

(ii) Exports to countries where cotton yarn exports from India are under quantitative restrainst (EEC).

(iii) Cotton yarn of accounts 60s and above.

(iv) Where export obligation of cotton yarn has been undertaken against import of capital goods at concessional duty.

(b) Yes Sir. However, the Government from time to time weighs the benefits from exports of cotton yarn *vis-a-vis* the requirements of decentralised sector and takes steps to make a balance between various competing national interests.

कोल इंडिया लि० की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति

350. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन को 1989–90 और 1990–91 की वर्षों तथा 1991–92 की प्रथम छमाही में कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आर्थिक हानि को देखते हुए सरकार

ने इस संगठन को प्रशासनिक व्यय कम करने व कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संगठन द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इन कदमों के फलस्वरूप इस संगठन को कितना लाभ होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) कोल इंडिया लि० की स्थापना किए जाने से, वर्ष 1981–82 तथा वर्ष 1989–90 के वर्षों को छोड़कर जबकि इसने लाभ कमाया, यह प्रतिवर्ष घाटा कमा रही है ।

(ख) वर्ष 1989–90 में कमाया गया लाभ/उठाया गया घाटा नीचे दिया गया है :–

1989–90 (+)80.13 करोड़ रु० (लाभ)

1990–91 और
1991–92 (अप्रैल–सितम्बर, 1991)

सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किफायती उपायों का अनुपालन किया गया है।

(घ) कोल इंडिया लि० के घाटे को रोके जाने के संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम तथा इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि किए जाने के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(2) उपयुक्त वर्कशाप स्पोर्ट, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार तथा उपकरणों के समय पर पुर्नवासन द्वारा उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार।

(3) श्रमशक्ति, आयोजन में सुधार, जिसमें अतिरिक्त श्रमशक्ति का पुनः नियोजन तथा प्राकृतिक अपशिष्टता के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कामगारों को लिए जाने पर प्रतिबंध शामिल है।

(4) ब्लास्टिंग कार्य क्षमता में सुधार विद्युत मुद्दे तथा सूची-नियंत्रण में सुधार करके विभिन्न अन्य खानों तथा कलपुर्जों के उपभोग में किफायत।

(5) लागत में कमी किए जाने संबंधी उपायों की निगरानी में सुधार।

(6) राज्य विद्युत बोर्डों जैसे बड़े उपभोक्ताओं की ओर कुल बकाया देय राशि को कम किए जाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) प्रणाली सुधार तथा प्रबंधन उपायों के संबंध में कई उपाय अंगीकृत किए गए हैं, ताकि कार्यचालन की कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके।

(8) उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए विद्यमान खानों के पुनर्गठन के संबंध में प्रयास।

इस समय वर्ष के दौरान होने वाले लाभ अथवा होने वाली संभावित हानि के संबंध में अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।